

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-3/जे0डी0/जीबीएन-13(गा0बाद) 2

दिनांक: जनवरी

09

,2013

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-08 कासिंग रिपब्लिक ग्राम डूडाहेडा जिला गाजियाबाद में प्रस्तावित एल0आई0जी0 ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 07-01-2013 के माध्यम से प्रश्नगत एल0आई0जी0 आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 07-01-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण उपनिदेशक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांक: 08-01-2013 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1- कुल प्लॉट एरिया-10320.00 वर्ग मी0 है।

2- भूतल कवर्ड एरिया-2292.95 वर्ग मी0 है

क्रमांक	नाम ब्लाक	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	तलों की संख्या	ऊँचाई मी0 में
1	ब्लॉक-ए0-1	1730.907	भूतल एवं 08 तल	25.65
2	ब्लॉक-ए0-2	562.043	भूतल एवं 08 तल	25.65

भवन का अधिभोग विवरण:-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 45 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई-6.00 मी0 है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-09.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान दर्शाया गया है जिसको सदैव अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के टावर ए0-1 में 04 एवं टावर ए0-2 में 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.5 मी0 एन0बी0सी.0 के अनुसार प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

1-होजरील:- प्रस्तावित भवन प्रत्येक ब्लॉक/टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैंडिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-टेरिस टैंक: समस्त टावरों की टेरिस पर ऊँचाई के अनुसार टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

3-टेरिस पम्प: दोनों टावरों की टेरिस टैंक के पास 900 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4-डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन में 100 एमएम डायमीटर का डाउनकामर का प्राविधान तथा उस पर फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त टावरों में मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

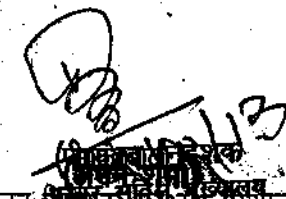
6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

7-एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-08 कासिंग रिपब्लिक ग्राम डूडाहेडा जिला गाजियाबाद में प्रस्तावित एल0आई0जी0 ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।


संयुक्त अग्निशमन विभाग, गजियाबाद
लेटर नं. 13

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-08 कासिंग रिपब्लिक ग्राम डूडाहेडा जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 355/एमपी/2013

दिनांक : 5-3-2013

मानचित्र संख्या : 1504/जोन-2/2011-12

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मै.क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (कन्सॉर्शियम),

क्रासिंग रिपब्लिक,

ग्राम डूंडाहेडा, एन.एच.24, गाजियाबाद

महोदय,

ग्राम-डूंडाहेडा में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी.एच.8 के 10320 वर्ग मी. भूमि पर प्रस्तुत 466 एल.आई.जी. (जी+8 मंजिलें) भवनों के निर्माण की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 17.12.12 को निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गई है-

- 1- यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
- 2- मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0 अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी किसी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 3- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- 4- यदि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा कोई भी व्यवसाय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 5- पूर्व में निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट दिनांक 03.02.07 की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
- 6- सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- 7- स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
- 8- वह मानचित्र 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
- 9- रैम्प का निर्माण अपनी ही भूमि पर सड़क अथवा लेन को बिना प्रभावित किये करना होगा।
- 10- सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन के नियम / शर्तों का पालन करना होगा।

(2)

- 11- भू-स्वामित्व हेतु प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्ष्यों के विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है अथवा कोई विवाद होता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माणकर्ता/ विकासकर्ता कम्पनी की स्वयं की होगी।
- 12- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनादेश दि. 28.11.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै० क्रासिंग इन्फ्रा० प्रा० लि० (कन्सोर्सियम) का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अधिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु रुपये 19.11 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डवलपमेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 21.01.14 व 28.03.13 तक है जो आवश्यकता अनुसार बढ़वानी होगी।
- 13- भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य बाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
- 14- भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, बाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णता प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
- 15- संदर्भित एल.आई.जी. भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
16. प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसको यथावत रखा जायेगा अथवा उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

(3)

17. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल खारिज बकाया है तो उसे विकासकर्ता कम्पनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा।
18. प्रस्तावित अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अधिकरण द्वारा निर्धारित लागत पर एवं निर्धारित मानकों के अनुसार विकसित/निर्मित कर उपलब्ध कराये जाएंगे। इन भूखण्डों/भवनों का आवंटन उक्त आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा। यदि कोई आवंटन किया गया है तो उसे निरस्त करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवंटन करना होगा।
19. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र के अनुसार तथा भवन की स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राईंग के अनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। योजना की पुनरीक्षित डी.पी.आर. एवं पुनरीक्षित तलपट मानचित्र दिनांक 18.01.2010 में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी /2001(आ.ब.) दि. 03.02.01, 72/9-आ-1 -2001- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दि. 13.02.01 तथा शा.सं. 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दि.20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
 क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
 ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रीट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

(M)

- ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता /आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-
- 1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - 2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
 - 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 - 4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राईंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
 - 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
 - 6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
 - 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
20. अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति पत्र एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
21. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग / निर्माण शमनीय नहीं होगा।
22. मानचित्र में प्रदर्शित लिफ्ट के संचालन हेतु कारप्स फंड का प्राविधान करना होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता कम्पनी की होगी। प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(5)

23. प्रस्तावित एल.आई.जी. के भवन निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश संख्या 5899/8-3-09-214 विविध/09 दिनांक 14.01.2010 के अनुसार रखनी होंगी।
24. अपार्टमेंट एक्ट 2010 का अनुपालन करना होगा।
25. दर्शाये गये पार्किंग प्लान में निर्माण के समय पार्किंग प्लान के अनुसार ग्रीड/पिलर्स की दूरी रखी जायेगी तथा शमन/पूर्णता प्रमाण पत्र के समय ग्रीड सहित पार्किंग प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
26. सम्पूर्ण परिसर का विकास कार्य पूर्ण होने एवं अन्तिम डिस्पोजल प्वाइन्ट तक निस्तारण होने के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही पूर्ण प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण परिसर का जारी किया जायेगा।
27. सैट बैंक में बालकनी के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है।
28. सम्पूर्ण टाउनशिप हेतु प्रदूषण विभाग, एअरपोर्ट एथोरिटी की अनापत्ति प्राप्त होने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
29. प्रस्तावित भवन में रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जमानत के रूप में जमा की गयी रूपये 2,00,000/- की धनराशि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंगके निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 30- आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता को निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि की शेष 80% धनराशि लेबर सैस के मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी अथवा शमन के समय उक्त मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- 31- उपरोक्त समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक : एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

M/5/5/13
मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा. गाजियाबाद

पत्रांक : /एमपी/1504/जोन-2/2011-12 दिनांक

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा. गाजियाबाद



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक/संख्या 101724/सी-1/सहमति वायु/जी-1771/2017

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० (कासिंग रिपब्लिक),
एन० एच०-24, डुडाहेडा (इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप),
गाजियाबाद।

विषय: विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ 98733/वायु सहमति/जी-1771/2017 दिनांक 24/03/17 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा उद्योग को दिनांक 31/12/2017 तक शर्त सहमति वायु प्रदान की गयी है। आपने पूर्व में वायु सहमति आवेदन पत्र 2019 तक किया गया था। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 28/3/2017 द्वारा सहमति बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को पूर्व में निर्गत वायु सहमति पत्रांक एफ 98733/वायु सहमति/जी-1771/2017 दिनांक 24/03/17 के साथ संलग्न सहमति वायु आदेश सं० 1771/सी-1/वायु सहमति आदेश/564/2017 दिनांक 22/3/2017 की वैधता अवधि दिनांक 31/12/2018 तक बढ़ाई जाती है। उक्त सहमति आदेश में निहित सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(डा० राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

अग्रवाल/-

टी.सी. - 12, वी, विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522 2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764 2720676
ई-मेल: info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828
Fax: 0522 - 2720764 -
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक/संख्या- 98732/सी-1/सहमति जल/जी-1983/2017

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स कासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 (कासिंग रिपब्लिक),
एन0 एच0-24, डुडाहेडा (इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप),
गाजियाबाद।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ 98732/सी-1/सहमति जल/जी-1983/2017/121 दिनांक 24/3/17 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा उद्योग को दिनांक 31/12/2017 तक सशर्त सहमति जल प्रदान की गयी है। आपने पूर्व में जल सहमति आवेदन पत्र 2019 तक किया गया था। उद्योग को वर्ष 2017 तक जल सहमति प्रदान की गयी थी। उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 28/07/2017 के माध्यम से उद्योग को वर्ष 2018 तक सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को पूर्व में निर्गत सहमति जल पत्रांक एफ 98732/सी-1/सहमति जल/जी-1983/2017/121 दिनांक 24/3/17 के साथ संलग्न सहमति जल आदेश सं0 1983/सी-1/जल सहमति आदेश/606/2017 दिनांक 22/03/2017 की वैधता अवधि दिनांक 31/12/2018 तक बढ़ाई जाती है। उक्त सहमति आदेश में निहित सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

अग्रवाल/-

टी.सी. - 12, वी, विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522 2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828
Fax: 0522 - 2720764 -
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : docuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Shri Ashok Kumar,
COO,
M/s Crossings Infrastructure Pvt. Ltd,
Glass Gate, Near ABES Engg. College,
NH-24, Dhundera, Ghaziabad, U.P.-201009

Ref. No. 2099...../Parya/SEAC/1608/2013/TA(J)Date: 12 October, 2013

Sub: Environmental Clearance for Expansion of Residential Township Project "Crossing Republik"
Village-Dundahera, NH-24, Bypass Ghaziabad, U.P. M/s Crossings Infrastructure Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 14/05/2013, 01/07/2013, 06/09/2013, 21/09/2013 and 04/10/2013 addressed to the Secretary, SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meetings held on dated 18/06/2013 and 04/10/2013.

A Presentation was made by the representatives of project proponents along with their consultant M/s ENV DAS India Pvt. Ltd. The project proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:

1. The Environmental Clearance is sought for proposed Expansion of Residential Township Crossing Republicat Village-Dundahera, NH-24, Ghaziabad, U.P.
2. Project proponent through their letter dated 06/09/2013 have provided Khasra details of the proposed project as 121-123, 125-130, 143-149, 286-288, 293-349, 434, 435, 437, 438, 538-559, 571-580, 582-586, 588-593, 595, 596, 598-607, 620-657, 661-670, 677-695, 697, 704-707, 1198, 1200-1205.
3. Area details of the project are as follows:

Particulars	Area (Sqm)	Area (Acres)
Total Township Area	14,56,873	360.0 acres
Master Plan Green	1,88,862	46.7 acres
Total Plot Area	12,68,011	313.3 acres

Particulars	Area (Sqm)	Percentage
Group housing	7,12,389.8	56.2%
EWS/LIG	66,420	5.2%
Commercial	1,93,732.7	15.3%
Education facility	79,005.13	6.2%
Medical facility	40,893.24	3.2%
Community center	7500	0.6%
Police Stn	21,600	1.7%
Fire Stn.	10,000	0.8%
LPG/ petrol Stn.	3000	0.2%
Telephone Ex./P.O.	5200	0.4%
Road Area	1,28,270.1	10.1%

4. Comparative Area statement from original proposals and expansion proposals are as follows:

	ORIGINAL PROPOSAL(sqm)		NEW EXPANDED PROPOSAL(sqm)	
Total Plot Area	14,56,873.2			
FAR				
Group Housing (18 Blocks)	10,68,784.95	FAR – 1.5	28,49,559.3	FAR – 4.0

Commercial	2,06,631.84	FAR - 1.2	7,74,930.8	FAR - 4.0
Institutional	1,17,068.63	FAR - 1.0	1,42,209.2	FAR - 1.8
EWS/LIG	48,373.5	FAR - 1.5	1,32,840.0	FAR - 2.0
Medical	39,789.6	FAR - 1.2	1,14,501.0	FAR - 2.8
Community	13,500.0	FAR - 1.5	11,250.0	FAR - 1.5
Others (Fire, Police etc.)	26,824.9		13,860.0	
Total FAR	15,20,973.5		40,39,150.4	
Basement Area	13,54,716.0		16,34,314.7	
Facilities (Non -FAR)	38,024.4		1,00,978.7	
Built Up Area	29,13,714		57,74,443.9	

5. Comparative Statement of Old and New facilities are as follows

PARTICULARS	ORIGINAL PROPOSAL	NEW EXPANDED PROPOSAL
Fresh Water	7.8 MLD	14.6 MLD
Recycled Water	6.6 MLD	6 MLD
Total Water Requirement	14.5 MLD	20.4 MLD
STP Capacity	CSTP of GDA	CSTP of GDA
Wastewater Generation	9.4 MLD	16 MLD
Source of Water Supply	Ground Water (till municipal supply is made available)	Ground Water & Ganga Jal (Applied)
Power Requirement	63 MW	85 MW
Backup Power (DG Sets)	7 numbers of D.G sets each of 1 MW capacity	7 numbers of D.G sets each of 1 MW capacity
Municipal Solid Waste	41 TPD	112 TPD
E- Waste		90 Kg/day
Biomedical Waste (500 beds)		825 Kg/day

6. Water requirement of the project are as follows:

Particulars	Unit/ Area	Population	Rate of Fresh Water supply norms	Fresh water KLD	Rate of Flushing Water supply	Flushing/ Recycled Water KLD	Total Water KLD
Residential	42500	212500	65 LPCD	13813	21 LPCD	4463	18275
Floating (10% of Resd.)		21250	5 LPCD	106	10 LPCD	213	319
Commercial	774931	77493	5 LPCD	387	10 LPCD	775	1162
School	142209	2000	15 LPCD	30	10 LPCD	20	50
Medical Facilities	114501	500 beds	340 Lit/Bed	170			170
Community Center	11250	750	5 LPCD	4	10 LPCD	8	11
Misc.				20			20
Landscape Area	152484.3					152	152
HVAC						200	200
DG Cooling						40	40
Total Water Requirement				14530		5870	20400

- Approx. 16 MLD waste water will be generated from the township which will be discharged into municipal sewer from where it will go into CSTP of GDA.
- Combined Sewage Treatment Plant (CSTP) of Ghaziabad Development Authority (GDA) is situated near the site. (Location is marked on the Layout Plan).
- Treated wastewater received from CSTP of GDA will be further treated at site for flushing, landscaping, Cooling and other low end uses.
- 7. The total water requirement is proposed as 20400 KLD which will be sourced from bore well/ Municipal Supply. Total fresh water requirement is proposed 14.6MLD.
- 8. The total waste water generation is proposed as 16 MLD treated in CSTP of GDA.
- 9. Total power requirement is proposed as 85 MW from UPPCL.
- 10. 7 nos. of DG Set of (71x MW) are proposed for power back up.
- 11. Total green area of the proposed project is 501000 m².
- 12. Solid Waste Management details are as follows:

Particulars	Population	Waste (TPD)
Residential	212500	106.3
Floating (10% of Residential)	21250	3.2
Commercial	77493 sqm	2.1
School	2000	0.5
Medical Facilities	500 beds	
Community Center	11250 sqm	0.3
Total Municipal Waste		112 TPD
Horticulture waste (@0.0037 kg/sqm/day)		1.85 TPD
E waste (@0.15 kg/c/year)		112 Kg/day
Biomedical Waste (500 beds)		825 Kg/day

- 13. The proposed number of rain water harvesting pits 380 will be provided.
- 14. The total excavated earth is 69354 m³.
- 15. Total No. of Block is 18.
- 16. The Project proposal falls under category 8"b" of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (meeting held on 04/10/2013), the State Level Environment Impact Assessment Authority (meeting held on 10/10/2013) has decided to grant the Environmental Clearance to the project subject to the effective implementation of the following general and specific conditions:

A. General Conditions:

1. The proposed project shall be in conformity to land use approved by competent Authority.
2. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
3. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U P pollution control board before start of construction.
4. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
5. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent Authority shall be obtained in this regards.
6. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent Authority.
7. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
8. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
9. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.

10. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
11. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
12. Obtain necessary clearances from the competent Authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
13. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
14. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
15. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
- ✓ 16. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
- ✓ 17. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
- ✓ 18. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
19. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
20. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
21. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
22. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
23. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
24. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
25. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
26. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
27. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
28. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
29. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
30. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
31. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
32. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
33. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.

34. Prepare and present disaster management plan.
35. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
36. A report on the energy conservation measures conforming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
37. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
38. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
39. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
40. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
41. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
42. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
43. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority.
44. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
45. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
46. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
47. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
48. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.
49. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
50. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
51. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
52. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
53. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
54. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
55. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
56. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
57. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
58. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.

59. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
60. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
61. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
62. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
63. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
64. Dispensary for first aid shall be provided.
65. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
66. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
67. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
68. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
69. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
70. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
71. Project proponents shall endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purposes and compliance.
72. Appropriate safety measures should be made for accidental fire.
73. Smoke meters should be installed as warning measures for accidental fires.
74. Plan for safe disposal of R.O reject is to be submitted.
75. Project falling within 10 K.M. area of Wild Life Sanctuary should obtain a clearance from National Board for Wild Life (NBWL) even if the eco- sensitive zone is not earmarked.

B. Specific Conditions:

1. The project proponent will ensure that no fresh ground breaking is undertaken in 500 m from any environmental sensitive features.
2. The project proponent will not undergo any construction activities before all litigation related to project in respect of Municipal Solid Waste dump site of Dhundera are finally resolved.
3. The court decision related to litigation to project shall be final and implemented.
4. The project proponent will submit Corporate Social Responsibility (CSR) Plan amounting 2% of project Cost within 3 months or any way before commencement of construction.
5. Ground water recharging will be strictly followed.
6. Digging of basement shall be undertaken in view of structural safety of adjacent buildings under information/consultation with District Administration/Mining Department.
7. Sprinkler to be used for curing and quenching during construction phase. No ground water to be used for construction.
8. During the construction phase, a wheel wash arrangement shall be provided at all exit points of the site.
9. Environmental Corporate Responsibility (ECR) plan along with budgetary provision amounting to 2% of total project cost shall be submitted (within three month) on need base assessment study in the study area. Income generating measures which can help in up-liftment of weaker section of society consistent with the traditional skills of the people identified. The program can include activities such as old age homes, rain water harvesting provisions in nearby areas, development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. In addition, vocational training for individuals shall be imparted so that poor section of society can take up self employment and jobs. Separate budget for community development activities and income generating programmers shall be specified.
10. Use of LEDs should be ensured in place of CFL. Solar light is to be provided in the common areas with 50% of them may be with dual power.

11. Motion sensor based lights to be provided in parking areas, corridors, passages, aisles, stairways.
12. Photoelectric lighting should be provided on all the open areas/roads.
13. All internal and peripheral roads should be minimum 9 m. wide and all entry & exit should be bell mouth shaped.
14. The three tier Green Belt shall be raised all around the plant site which shall comprise of not less than 33% of the total area. The project proponent shall ensure that the density of trees are not less than 2500 per ha and rate of survival of plantation shall be not less than 80%. The selection of plant species shall be as per the CPCB guidelines in consultation with the DFO.
15. STP to be constructed during construction phase. 100% waste water is to be treated in STP conforming to prescribe standards of receiving body or designated use. Monitoring of STP to be done weekly till its stabilizations then monthly. The excess treated waste water after in-house use may be given to nearby builders for construction or discharge into public drainage system/drains after permission from the competent authority
16. As committed during presentation zero discharge (no effluent outside the project) be achieved
17. 100 % provision of Rain Water Harvesting is to be made. RWH shall be initially done only from the roof top. RWH from green and other open areas shall be done only after permission from CGWB. RWH pits shall be relocated towards wider open area available for ground water recharge.
18. Dedicated guest parking at surface should be provided.
19. Manure generated from STP/organic waste converter shall be used in-house and plan for management of surplus be submitted within three (3) months.
20. Stack Height should be calculated based on combined D.G. sets capacity and shall be higher than the tallest building in the project.
21. The total excavated soil will be completely utilized at project site for leveling and back filling. The top soil generated during basement construction will be used for plantation and green area development. The management of surplus soil, if any, will be transported and managed in Eco-friendly manner and the plan will be submitted within 3 month.
22. Crèche to be provided during the construction and operation phase.
23. Provision of separate dedicated room to be made for senior citizen commensurate with proper amenities (TV, music system, indoor games etc.) for end user in and around the club house.
24. E-waste shall be managed as per e-waste Management and Handling Rules 2011. Temporary storage at secure place is made till it is given to recycler approved by CPCB.
25. A temporary separate and isolated MSW storage and transfer room should be provided at least for two days in a manner to avoid generation of foul smell.
26. Ground water should not be extracted for the purpose of construction or otherwise. In case of default the Environmental Clearance will deem to be cancelled.
- ✓27. Post project monitoring for air, water (surface+ground), Stack (including CO and HC) noise and STP to be carried out as CPCB/SPCB guidelines.
28. Adequate Ventilation arrangement in the basement should be provided along with installation of CO Monitors.
29. The basement should be constructed in consultation with CGWB to avoid any infringement of ground water table.
30. Project falling within 10 Km. area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
31. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any Wetlands/Ponds within the project area as per revenue records if any should be protected and brought to the notice of forest department / SEIAA for directions.

32. Project proponent should procure all the regulatory clearances and completion certificate from the development authority before handing over the possession of dwellings to residents.
33. The project proponent to ensure that buffer zone of no activity/development as declared /identified under any law does not fall around the project boundary.

It shall be ensured that proposed power backup for the project should be less than 05 MW. Also, no construction is to be started without obtaining Prior Environmental Clearance. Concealing factual data and information or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions stipulated in the Prior Environmental Clearance attract action under the provision of Environmental (Protection) Act, 1986.

This environmental clearance is subject to ownership of the site by the project proponents in confirmation with approved Master Plan for Ghaziabad by the competent Authority. In case of violation, it would not be effective and would automatically stand cancelled.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary. Necessary statutory clearances should be obtained.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in the matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.


(J.S. Yadav)

Member Secretary, SEIAA

Dated: As above

No...../Parya/SEAC/1608/2013/TA(J)

Copy for Information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Chief Conservator, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. District Magistrate, Ghaziabad, U.P.
6. Deputy Director, Regional Office, Directorate of Environment, Meerut.
7. Copy for Web Master/Guard file.


(O.P. Varma)

Director (I/c)/Secretary, SEAC
Directorate of Environment